Editorial

Sufferings of BSNL Employees

At present about sixty two thousand employees are working in BSNL adding both executives and non-executives. Out of this strength about thirty two thousands non-executive employees are on roll today in BSNL. These employees are also of two streams, one who have been transferred from department of Telecom and absorbed in BSNL and others are direct recruited by BSNL.

At present these two types of employees are facing a grim situation for non obviation of HR issues related to them. Some burning H.R. related issues are as fallows which has hurt the employees and due to this, demotivation have developed among the work force.

1. **Pay revision/wage revision —** The hike in salary needed by all the workers. As per provision to implement pay revision and wage revision the employees of loss making – PSUs are not entitle to get their wages revised. One side the period of wage revision is fixed for Ten Years and other side after completion of Ten years it is told that due to provision of affordability clause in DPE guide lines issued for pay revision/wage revision of PSU's the BSNL employees are not coming under the provision of guide line hence the wage revision is not possible.

   Both the section of employees either of executives and non executives are deprived due to non implementation of 3rd wage revision in BSNL. The hard working of employees are not being taken under consideration and the imaginary guide lines of DPE is being treated as the spiritual truth for the management/Govt. The planning and development is the look out of the management and govt. but the poor employees who are contributing continuously are deprived for the loss of the company. It is not fare at the part of management as well the Govt. at centre.

   Only for eye wash the management has constituted a wage revision committee, but the motive of the members of management side reflects that hike in salary will not be allowed for the workers.

   It is most discrimatory that the Top level officer working on deputation for full of their service period are getting all the benefits of 7th CPC from the BSNL hard earned money but the employees in the same company are deprived their legitimate right of wage hike even after Ten years.

2. **Stagnation —** At present out of eighteen thousand absorbed employees more than nine thousand are facing stagnation but the BSNL management is not taking it under consideration as on abnormal situation. Our union has continuously raised this issue with Top level of management, but all have gone in vain.

   The large number of stagnation have come mostly due to implementation of 72.8 IDA merger with effect from 1st January 2007. The fixation was made notionally based on the 9.4% hike w.e.f. 01-01-2007 but the scale framed on 01.01.2007 based on 68.8% IDA was left without change. In June 2013, when 78.2% IDA based 9.4% hike was given to employees in their salary, it effected a huge stagnation.

3. L.I.C.E. for promotion to workers of non executive is also a burning issue of the employees which is not taken by the management in right perspective. In so called restructuring of staff strength the post of each cadre has been reduced drastically by the management in the period of Covid -19 pandemic. Even the sanction was given less than the working strength of the employees causing a big hardship to serving employees. As getting promotion even on merit basis in BSNL is looks impossible.

4. **Compassionate appointment —** On CGA ban was imposed for three years from 2019 to 31st March 2022. On completion of three years again it has been imposed ban till further orders from 1st April 2022. Besides these, a number of burning H.R. issues are pending which is badly effecting the motivation of work force.

   The working class have experience of past that without united struggle nothing is easily possible to get. The workers must be united and move forward to protect their rights. Our organization as its tradition is always stand with the workers in front line to save their interest and protect their rights.

Workers Unity Zindabad.

Long live BSNL - NFTE Zindabad

संपादकीय

बी0एस0एन0एल0 कर्मचारियों की पीड़ा

वर्तमान में बीएसएनएल में लगभग 62000 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें कार्यपालक और गैर कार्यपालक दोनों शामिल हैं। इस संख्या में से लगभग 32000 गैर कार्यपालक कर्मचारी बीएसएनएल में कार्यरत हैं। ये कर्मचारी भी दो धाराओं के हैं एक जिनका तबादला दूरसंचार विभाग से किया गया है और अन्य बीएसएनएल द्वारा सीधे भर्ती किये जाते हैं।

वर्तमान में इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों को एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एचआर से संबंधित कुछ ज्वलंत मुद्दे इस प्रकार हैं जो कर्मचारियों को आहत करते हैं और इसके कारण कार्यबल के बीच निराशाएं विकसित हुई हैं।

1) वेतन संशोधन – उच्च वेतन में वृद्धि सभी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। वेतन संशोधन को लागू करने के प्रावधान के अनुसार घाटे में चल रहे पीएसयू के कर्मचारी अपने वेतन को संशोधित करने के हकदार नहीं हैं। एक तरफ वेतन संशोधन करने की अवधि दस साल है और दूसरी तरफ दस साल पूरा होने के बाद कहा जाता है कि वेतन संशोधन के लिए जारी डीपीई गाईड लाईन में सामर्थ खंड के प्रावधान के लिए बीएसएनएल के कर्मचारी गाईड लाईन के प्रावधान के तहत नहीं आ रहे हैं, इसलिए वेतन संशोधन संभव नहीं है।

बीएसएनएल के वेतन संशोधन को लागू न करने के कारण कर्मचारियों के दोनो वर्ग अधिकारी और गैर अधिकारी वंचित हैं। कर्मचारियों के मेहनत को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और प्रबंधन/सरकार के द्वारा डीपीई की काल्पनिक गाईड लाईन को अध्यात्मिक सत्य माना जा रहा है। योजना और विकास पर सरकार की नजर है लेकिन जो गरीब कर्मचारी लगातार योगदान दे रहे हैं उनके हितों की अनदेखी प्रबंधन/सरकार द्वारा की जा रही है। केवल धोखा देने के लिए प्रबंधन ने वेतन संशोधन कमीटी का गठन किया है लेकिन प्रबन्धन पक्ष के सदस्यों का मकसद यह दर्शाता है कि श्रमिकों की वेतन में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जायेगी।

यह सबसे भेदभाव पूर्ण बात है कि अपनी पूरी सेवा अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले उच्च स्तर के अधिकारी को बीएसएनएल की गाड़ी कमाई से सातवें वेतन आयोग्य के सभी लाभ मिल रहे हैं लेकिन एक ही कंपनी के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के अपने जायज अधिकार के लिए विउत्पन्न किया जाता है।

2) वेतन ठहराव वर्तमान में अठारह हजार में से नौ हजार से अधिक कर्मचारियों को वेतन बढ़ोत्तरी ठप्प कर दिया गया है, लेकिन बीएसएनएल प्रबंधन असामान्य स्थिति पर विचार नहीं कर रहा है। हमारे संघ ने लगातार इस मुद्दे को शीर्ष स्तर के प्रबंधन के साथ लगातार उठाया है लेकिन प्रयास बेकार जा रहे हैं।

3) 1 जनवरी 2007 से प्रभावी 72.8 आईडीए विलय के कार्यान्वयन के कारण बड़ी संख्या में ठहराव आया है। निर्धारण 9.4% के आधार पर दिनांक 01.01.2007 से किया गया था, लेकिन 01.01.2007 को स्केल तैयार किया गया था। 2007 68.8% पर आधारित आईडीए बिना बदले छोड़ दिया गया था। जून 2013 में जब कर्मचारियों को उनके वेतन में 78.2 प्रतिशत आईडीए आधारित 9.4 प्रतिशत वृद्धि दी गई, तो इसने एक बहुत बड़ा ठहराव प्रभावित किया।

4) एल.आई.सी. ई–गैर–कार्यपालक के कर्मचारी की पदोन्नति के लिए भी कर्मचारियों का एक ज्वलंत मुद्दा है जिसे प्रबंधन द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जाता है। कर्मचारियों की संख्या के तथाकथित पुनर्गठन में प्रबंधन द्वारा कोविड –19 महामारी की अवधि में प्रत्येक संवर्ग के पद को काफी कम कर दिया गया है। यहां तक कि मंजूरी भी काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से कम दी गई, जिससे कर्मचारियों को दक्षता के बावजूद पदोन्नति पाना असंभव प्रतीत हो रहा है। बीएसएनएल में योग्यता के आधार पर भी पदोन्नति असंभव दिख रही है। अनुकंपा नियुक्ति – सीजीए पर 2019 से 31 मार्च 2022 तक तीन साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। तीन साल पूरे होने पर इसे 1 अप्रैल 2022 से अगले आदेश तक पुनः रोक लगाया गया है। इनके अलावा कई ज्वलंत एचआर मुद्दे लंबित हैं जो बुरी तरह से कार्यबल की प्रेरणा को प्रभावित कर कर रहा है।

मजदूर वर्ग को अतीत का अनुभव है कि संयुक्त संघर्ष के बिना कुछ भी आसानी से प्राप्त करना संभव नहीं है। मजदूरों को एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारा संगठन अपनी परंपरा के रूप में श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा है।

मजदूर एकता जिंदाबाद।